(a) whether Government are aware of the growing degradation of forests in several parts of the country;

(b) if so, the steps taken to identify the reasons and save the forest and forest wealth from degradation and destruction; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) As per the state of Forest Report 1993 of the Forest Survey of India there is an overall increase of 925 Sq. Kms. of forest in the country. This includes increase in the dense forest cover by 568 Sq. Kms. over the 1991 assessment of the forest cover.

However, the main reasons identified for the degradation of the forests in the country include illegal removal of fuelwood foddar, timber and other non-timber forest produce due to increasing biotic pressures of growing human and cattle populations on forests. Quarrying, mining, laying of transmission lines and certain other developmental activities and encroachments also result in degradation of forests. Forest fires, floods, droughts and lendslides are also important reasons of degradation of forests.

(c) The measures adopted to prevent degradation of the forests in the country are:

(1) Indian Forests Act, 1927 and Wildlife (Protection) Act, 1972 are in force.

(2) There is a check exercised by the Government of India on diversion of forest land for non-forestry purposes under the provisions of Forests (Conservation) Act, 1980.

(3) Modern means of communications like wireless sets, fast speed vehicles etc. are provided to protective staff. Flying squads patrol sensitive areas to check illicit removal of forest produce.

(4) Joint Forest Management has been introduced in the country to allow people's participation in the management forest.

(5) Use of gobar gas and natural gas as alternatives to fuelwood is encouraged.

(6) Fuel efficient chulahs are introduced in the habitations surrounding forests.

(7) Massive afforestation programmes have been launched in different states to regenerate degraded forest areas.

(8) Wood substitutes and recycling of materials is encouraged to reduce pressure on forests.

(9) Awareness campaigns are organised to protect tree growth.

Scheme for construction of buildings in forest area in Kerala

287. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether any request is pending before Government received from the Kerala Government for sanction to construct buildings in the forest area near Sabarimala, a pilgrimage centre in Kerala so as to accommodate the devotees staying there during night hours; and

(b) if so, what are the details thereof and by when a final decision would be taken thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) The State Govt. of Kerala has submitted a proposal for diversion of 115.60 ha. of forest land under the Forest

(Conservation) Act, 1980 for providing amenities to the pilgrims of Sabarimala Temple in district Pathanamthitta. The proposed area forms part of Periyar Tigre Reserve. The site inspection of the forest area involved has been carried out by a team comprising officials of Central Government as well as State Government. After examination of the report of the above said team, it has been observed that the Committee on Environment (1993-95) of the IX Kerala Legislative Assembly is also seized of the matter. This Ministry has, therefore, asked the State Government to send a copy of the report of the above said Committee on Environment and also to inform the action that the State Government proposes to take on its various recommendations. The comments of the State Government on the report of the Central Team have also been solicited. Under these above circumstances a final decision cannot be taken at the moment.

गुजरात में तेल भंडार

288. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में अब तक किन-किन स्थानों पर तेल के भंडार का पता चला है और उनमें तेल और प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा उपलब्ध है;

(ख) इनमें से प्रति माह औसतन कितनी मात्रा में तेल निकाला जाता है और अब तक कितनी मात्रा में तेल निकाला गया है;

(ग) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र के जामनगर जिले में तेल और प्राकृतिक गैस के विपुल भंडार का पता चला है;

(घ) क्या कुछ विदेशी तथा भारतीय निजी कम्पनियों ने तेल और प्राकृतिक गैस निकालने के कार्य में अपनी रूचि दर्शाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): गुजरात राज्य में अन्वेषण प्रयासों के परिणामस्वरूप 78 तेल तथा/अथवा गैस के संभावना क्षेत्रों का पता चला है जिसके परिणामस्वरूप तेल तथा गैस के समतुल्य तेल (ओ+ ओ ई जी) की 1108.94 एम एम टी मात्रा के आरंभिक स्थानीय भंडार सिद्ध हुए हैं। इन हाइड्रोकार्बन संभावना वाले क्षेत्रों की सूची संलग्न विवरण में दी है। **(नीचे देखिए)**।

(ख) 1 अप्रैल, 1995 से 31 अक्तूबर, 1995 तक की अवधि के दौरान प्रति माह औसत उत्पादन लगभग 529,900 टन था। गुजरात राज्य में 31 मार्च, 1995 तक संचयी क्रूड आयल उत्पादन (कन्डेन्सेट सहित) 127.61 एम एम टी था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) चौथे दौर की बोली के अंतर्गत भारत सरकार ने गुजरात कच्छ तटीय बेसिन में ब्लाक जी के-ओ एन-90/2 में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए मैसर्स पैन इनर्जी रीसोर्सेज, यू एसए, स्टर्लिंग रीसोर्सेज, आस्ट्रेलिया, ओकलैंड आयल कंपनी, यू०एस०ए०, पैन पेसफिक पेट्रोलियम एन एल, आस्ट्रेलिया और ट्रांस एशिया कन्सल्टेंस इंडिया को ठेका दिए जाने का अनुमोदन किया है। ठेके पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

पांचवें दौर की बोली के अन्तर्गत भारत सरकार ने ब्लाक जी के-ओ एस/5 में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए मैसर्स रैक्सवुड-ओकलैंड कारपोरेशन, यू एस ए को ठेका दिए जाने का अनुमोदन किया है। ठेके पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

छठे दौर की बोली के अन्तर्गत भारत सरकार ने तटीय ब्लाक सी बी-ओ एन/2 के लिए मैसर्स सैम्सन इन्टरनैशनल लिमिटेड, यू एस ए, एच ओ ई सी बौड़दा और जी एस पी सी अहमदाबाद के परिसंघ को, तटीय ब्लाक सी बी-ओ एन/7 के लिए सैम्सन इन्टरनैशनल लिमिटेड, यू एस ए को तथा अपतटीय ब्लाक सी बी-ओ एस/1 के लिए वाल्को एनर्जी इंक, यू एस ए, टाटा पेट्राडाइन (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली और एच ओ ई सी बड़ौदा के परिसंघ को ठेका दिए जाने को अनुमोदन दिया है।

सातवें दौर के अन्तर्गत कैम्बे अपतट में 5 ब्लाकों (सी बी—ओ एन/1, सी बी-ओ एन/3, सी बी-ओ एन/4, सी बी-ओ एन/5, सी बी-ओ एन/6) के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। ये बोलियां सरकार के विचाराधीन हैं।

संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात कच्छ अपतटीय क्षेत्र में जी के-ओ एस जे-1 और जी